



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Page 250
K.M.-27
Deptt - 100
EPB 123

पूरा किया

सं. 99]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2010/चैत्र 26, 1932

No. 99]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2010/CHAITRA 26, 1932

प्रचारी
रा. वि. एक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2010

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित अजोडिकार्बोनामाइड (एडीसी) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/7/2010-डीजीएडी.—यतः मै. डेमैको पॉलिमर्स लि., नई दिल्ली (जिन्हें एतदपश्चात् आवेदक कहा गया है) ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् नियम कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित अजोडिकार्बोनामाइड (एडीसी) (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

1. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद अजोडिकार्बोनामाइड (एडीसी) है जिसे फुलाने वाले एजेंट अथवा झाग बनाने वाले एजेंट के रूप में जाना जाता है। फुलाने वाला परिशोधित एजेंट जिसमें एडीसी की 2-5% तक मात्रा होती है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आता है। संबद्ध वस्तुओं को पीवीसी उद्योग, रबड़ उद्योग इत्यादि में फुलाने वाले और झाग वाले एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

संबद्ध वस्तुओं का आयात भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत वस्तु विवरण तथा कोडिंग प्रणाली पर आधारित) के तहत उपशीर्ष 29270090, 29470090 तथा 381200890 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 और 38 के तहत किया जाता है। तथापि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद का कोई विशिष्ट सीमाशुल्क वर्गीकरण कोड नहीं है और उनका आयात विभिन्न अन्य सीमाशुल्क उप-शीर्षों के अंतर्गत किया जा रहा है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से इस जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग की स्थिति

यह आवेदन मै. डेमेको पॉलिमर्स लि., नई दिल्ली द्वारा दायर किया गया है। इसके अलावा चार अन्य विनिर्माताओं अर्थात् मै. श्री द्वारकाधीश (प्रा.) लि. (जिसे पूर्व में मै. एसएसएस पॉलिमर्स प्रा. लि. के नाम से जाना जाता था), मै. शर्मा ब्रदर्स प्रा. लि., मै. एस एस ब्लोकेम प्रा. लि. तथा मै. हरियाणा पॉलिमर्स लि. ने आवेदन को अपना समर्थन दिया है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने नोट किया है कि भारतीय उत्पादन में आवेदक कंपनी का एक प्रमुख हिस्सा है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियम 2 के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग हैं और आवेदन उपर्युक्त नियम 5 के संदर्भ में मानदंडों को पूरा करता है।

3. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है।

4. समान वस्तु

आवेदक ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा चीन जन. गण. से निर्यातित वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। वास्तविक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण इत्यादि जैसे मानदंडों के संबंध में दोनों उत्पादों की विशेषताएँ तुलनीय हैं। उत्पाद के मूलभूत गुणधर्मों के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ, चीन जन. गण. से आयातित वस्तुओं से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ चीन जन. गण. से आयातित वस्तुओं के समान वस्तु हैं।

5. सामान्य मूल्य

आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने निवेदन किया है कि चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में वे पर्याप्त सूचना नहीं जुटा पाए हैं। अतः आवेदक ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और लाभ सहित उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। तथापि प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त निर्धारण के प्रयोजनार्थ एक उपयुक्त तीसरे देश को आधार बनाया जा सकता है और उचित समय पर हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया जा सकता है। आवेदक द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद है।

6. निर्यात कीमत

आईबीआईएस से प्राप्त सौदेवार आयात आंकड़ों पर विचार करके संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का अनुमान लगाया गया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए निर्यातक देश में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन और पत्तन व्ययों के आधार पर समायोजन किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं।

7. पाटन मार्जिन

कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना की गई है जिसमें संबद्ध देश के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य, कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत से बहुत अधिक है, जिसमें प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन अनुमानित रूप से न्यूनतम सीमा से अधिक है।

8. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

आवेदक ने वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्डों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है। सूचना के विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि जांच अवधि में संबद्ध देश से आयातों में समग्र अर्थों में और भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में भी वृद्धि हुई है। बाजार हिस्से में हानि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट, निवेश पर आय तथा नकद लाभ में अत्यधिक गिरावट आदि जैसे विभिन्न आर्थिक मानदण्डों से प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है। वस्तुतः घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक मानदण्डों से यह प्रदर्शित होता है कि क्षति अवधि के दौरान हानि में समग्र रूप में वृद्धि हुई है।

9. पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं इसलिए प्राधिकारी ऐसे किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच के लिए एतद्वारा इस जांच की शुरुआत करते हैं।

10. जांच की अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2008 से 30 सितम्बर, 2009 (12 माह) है। तथापि क्षति जांच अवधि में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

11. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार
कमरा नं. 250ए, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा में जांच से संगत निवेदन कर सकता है।

12. समय-सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों जिन्हें अलग से लिखा गया है, को यह सूचना उन्हें अलग से भेजे गए पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर भेजनी होगी। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय-सीमा में विस्तार हेतु किसी प्रकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियमावली के नियम 6(7) के संदर्भ में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है और यदि ऐसी

सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय सारांश वाली उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

Initiation Notification

New Delhi, the 16th April, 2010

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Azodicarbonamide (ADC) originating in or exported from China PR.

No. 14/7/2010-DGAD.—Whereas M/s Demaco Polymers Ltd. New Delhi (hereinafter referred to as applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), alleging dumping of Azodicarbonamide (ADC) (herein after referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as "subject country") and requested for initiation of Anti Dumping investigation for levy of the anti dumping duties on the subject goods.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present application is Azodicarbonamide (ADC) which is also known as blowing agent or foaming agent. Modified blowing agent which contains 2 -5% of ADC is outside the purview of the product under consideration. The subject goods is used as a blowing and foaming agent in PVC industry, Rubber Industry etc.

The subject goods are being imported under Chapter 29 and 38 of the Customs Tariff Act under subheading 29270090, 29420090 and 381200890 under the Indian Trade Classification (based on Harmonized Commodity Description and

1418 GI/10-2

Coding System). The petitioner has, however claimed that the product under consideration does not have any dedicated customs classification code and are being imported under various other Customs sub-headings. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

2. **DOMESTIC INDUSTRY STANDING**

The application has been filed by M/s. Demaco Polymers Ltd., New Delhi. Further, the application has been supported by four other manufacturer namely, M/s. Sri Dwarka Dheesh (Pvt) Ltd., (formerly known as M/s. SAS Polymers Pvt. Ltd.), M/s. Sharma Brothers Pvt. Ltd., M/s. S.S. Blowchem Pvt. Ltd., and M/s. Haryana Polymers Ltd. On the basis of information available the Authority notes that the applicant company constitutes a major proportion in the Indian production. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes domestic Industry within the meaning of the Rule 2 and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

3. **COUNTRY INVOLVED**

The country involved in the present investigation is People's Republic of China.

4. **LIKE ARTICLE**

The applicant has claimed that there are no known differences in the subject goods produced by the petitioner and exported from China PR. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. The goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from China PR in terms of essential product properties. The goods offered by the domestic industry are like article to the goods imported from China PR.

5. **NORMAL VALUE**

The applicant has claimed that China PR should be treated as Non Market Economy and therefore the Normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annex-I of the AD Rules. The applicant has submitted that they have not been able to get the sufficient information regarding market economy third country for determination of Normal value in case of China PR. Thus, the applicant has claimed the Normal value on the basis of constructed cost of production, including selling general and administration expenses and profits. The Authority may however adopt an appropriate third country for the purpose of the above determination and notify the interested parties in due course. There is sufficient prima facie evidence with regard to normal value claimed by the petitioner.

6. EXPORT PRICE

Export price of the subject goods from the subject country has been estimated by considering transaction-wise import data from IBIS. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, and port expenses in the exporting country to arrive at ex-factory export price. There is sufficient prima facie evidence with regard to export price claimed by the petitioner.

7. DUMPING MARGIN

Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in China PR is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above *de minimis*.

8. INJURY AND CAUSAL LINK

The applicant has furnished information on various parameters relating to material injury. Analysis of the information shows that imports from subject country have increased in the period of investigation in absolute term as also in relation to production and consumption in India. Various economic parameters like the loss in market share, significant decline in the profitability of the domestic industry, significant deterioration in return on investment and cash profit, prima facie, indicate collectively that the domestic industry has suffered material injury on account of dumped imports of subject goods from China PR. In fact, various economic parameters relating to the domestic industry shows that loss in absolute term increased during the injury period.

9. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

In view of the above the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist and therefore the Authority, in terms of Rule 5 of the Anti Dumping Rules hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and recommend the amount of anti dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

10. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

The period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st October 2008 to 30th September 2009 (12 months). The injury investigation period will, however, cover the period 2006-07, 2007-08, 2008-09 and the POI.

11. SUBMISSION OF INFORMATION

The producers/exporters in the subject country, Government through the Embassy, importers in India known to be concerned with this investigation and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

**The Designated Authority
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Government of India,
Room No. 250A, Udyog Bhavan,
New Delhi – 110011.**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

12. TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

13. SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

In terms of Rule 6(7) of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

14. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority